

उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुमाग—3 अधिसूचना 09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 91/XVIII(3)/2016—20(01)/2014—श्री राज्यपाल महोदय, मूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन किये जाने हेतु निम्नवत् एक स्वतंत्र बहु—शाखीय विशेषज्ञ समूह गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्—

1.	संबंधित मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष,
2.	संबंधित क्षेत्र पंचायत प्रमुख	सदस्य.
3.	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित दो समाजिक विज्ञानी	सदस्य,
4.	संबंधित जिला पंचायत सदस्य	सदस्य,
5.	संबंधित मुख्य नगर अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी	
	नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम	सदस्य,
6.	परियोजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग के केन्द्र तथा	
	राज्य सरकार के जिला स्तर का अधिकारी	सदस्य-सचिव,
7.	संबंधित जिले के किसी महाविद्यालय या तकनीकी	
	शिक्षण संस्थान आदि से जिलाधिकारी द्वारा नामित	
	पुनर्विस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ	सदस्य।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त विशेषज्ञ समूह अपनी संस्तुतियां प्रकाशन एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

> क्षाज्ञा से, डीo एसo गर्ब्याल,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 91/XVIII(III)/2016-20(01)/2014, dated February 09, 2016 for general information:

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 91/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 7 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following independent multy disciplinary expert group for evaluation of Social impact Assessment Study:

1.	Concerning Chief Development Officer	Chairman,
2	Concerning Kshetra Panchayat Pramukh	Member,
3.	Two Social Scientist nominated by the concerning district Magistrate	Member,
4.	Concerning member of district Panchayat	Member,

 Concerning chief urban officer or executive officer of the Nagar Panchayat/Nagarpalika/Nagar Nigam

Member,

6. District level officer of center and State Government of the concerning administrative department of the project

Member.

 Two expert on rehabilitation nominated by the district magistrate from any degree college or technical institutions on teaching institutions of the concerning district

Member.

2. The Governor is also pleased that the above expert group shall provide his recommendations to the concerning district magistrate for publication and further proceeding.

By Order,

D. S. GARBYAL, Secretary.